



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 जनवरी, 2021

माघ 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 02/ग्यारह-2-21-9(42)-17-उ०प्र० जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश(172)-2021

लखनऊ, 29 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-60

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

### उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अड़तालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अड़तालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी। (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह नियमावली तारीख 22 दिसंबर, 2020 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
2. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 8 में, उपनियम (4क) के स्थान पर, अधिसूचित किये जाने की तारीख से निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	नियम 8 का संशोधन

	<p>“(4क) नियम (4) के अधीन दिए गये प्रत्येक आवेदन के पश्चात, जहां आवेदक कोई व्यक्ति हो अथवा जहां आवेदक कोई व्यक्ति नहीं है वहां धारा 25 की उपधारा (6क) के अधीन यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में आने वाले ऐसे व्यक्तियों का--</p> <p>(क) बायोमैट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन और फोटोग्राफ तब तक लिया जाएगा, जब तक कि वह धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो, यदि उसने अपने आधार संख्या के अधिप्रमाणन का विकल्प दिया हो तो; या</p> <p>(ख) यथा अधिसूचित, बायोमैट्रिक सूचना, तथा फोटोग्राफ लिया जाएगा और ऐसे अन्य केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन तब तक किया जाएगा, जब तक कि वह धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो, यदि उसने आधार अधिप्रमाणन का विकल्प नहीं चुना है, और साथ ही <b>प्रारूप जीएसटी आरईजी -01</b> में दिए गए आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियों का, इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र में, सत्यापन किया जाएगा और ऐसे आवेदन को तभी पूरा माना जाएगा जब इस उपनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो जाती है।”</p>
नियम 9 का संशोधन	<p>3. उक्त नियमावली में, नियम 9 में,-</p> <p>(क) उपनियम (1) में-</p> <p>(i) शब्द “आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से” के पश्चात शब्द “तीन” के स्थान पर शब्द “सात” रख दिया जाएगा;</p> <p>(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रख दिया जायेगा, अर्थात्:-</p> <p>“परंतु जहाँ-</p> <p>(क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या के अधिप्रमाणन से चूक जाता है या आधार संख्या के अधिप्रमाणन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या</p> <p>(ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जो कि सहायक आयुक्त से निम्न पद का न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो,</p> <p>नियम 25 के अधीन दी गई रीति से, उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराये जाने के पश्चात तथा जैसा समुचित अधिकारी उचित समझे, ऐसे कागजातों का सत्यापन किए जाने के पश्चात, आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।”;</p> <p>(ख) उपनियम (2) में,</p> <p>(i) शब्द “तीन” के स्थान पर शब्द “सात” को रख दिया जाएगा;</p> <p>(ii) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात्:-</p> <p>“परंतु जहाँ-</p>

<p>(क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन से चूक जाता है या आधार संख्या के अधिप्रमाणन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या</p> <p>(ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से, जो कि सहायक आयुक्त से निम्न पद का न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो,</p> <p>ऐसे आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों के भीतर प्रारूप जीएसटी आरईजी -03 में नोटिस जारी किया जा सकेगा।”;</p> <p>(ग) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम को रख दिया जाएगा, अर्थात् :-</p> <p>“(5) यदि समुचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने से चूक जाता है,-</p> <p>(क) आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर उस मामले में जहाँ कि ऐसा व्यक्ति उपनियम (1) को परंतुक के अधीन नहीं आता है तो; या</p> <p>(ख) आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जहाँ ऐसा व्यक्ति उपनियम (1) के परंतुक के अधीन आता हो तो ; या</p> <p>(ग) उपनियम (2) के अधीन आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण, जानकारी या दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के अवधि के भीतर तो,</p> <p>रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा।”</p>	
<p>4- उक्त नियमावली में, नियम 21 में,-</p> <p>(क) खंड (ख) में, शब्द “माल या सेवाओं” के पश्चात शब्द “या दोनों” बढ़ा दिये जायेंगे;</p> <p>(ख) खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंडों को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-</p> <p>“(ड) अधिनियम की धारा 16 और इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अतिक्रमण में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ प्राप्त करता है; या</p> <p>(च) धारा 37 के अधीन <b>प्रारूप जीएसटीआर- 1</b> में एक या एक से अधिक कर अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे उसके द्वारा संबन्धित कर अवधियों के लिए धारा 39 के अधीन प्रस्तुत की गई वैध विवरणी में घोषित किए गए जावक पूर्तियों के ब्यौरे से अधिक है; या</p> <p>(छ) नियम 86ख के उपबंधों का उल्लंघन करता है।”</p>	नियम 21 का संशोधन
<p>उक्त नियमावली में, नियम 21क में, -</p> <p>(क) उपनियम (2) में, शब्द “उक्त व्यक्ति को सुनवाई का यथोचित अवसर दिये जाने के पश्चात” को हटा दिया जाएगा;</p> <p>(ख) उपनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को बढ़ा दिया जाएगा: -</p>	नियम 21क का संशोधन

	<p>“(2क) जहाँ, धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की तुलना</p> <p>(क) <b>प्रारूप जीएसटीआर-1</b> में प्रस्तुत किए गए जावक पूर्तियों के ब्यौरे; या</p> <p>(ख) उसके पूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके <b>प्रारूप जीएसटीआर-1</b> में प्रस्तुत किए गए जावक पूर्तियों के ब्यौरे के आधार पर निष्कर्षित आवक पूर्तियों के ब्यौरे,</p> <p>या ऐसे अन्य विशलेषण, जो परिषद की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता हो कि ऐसी महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो, तो उसके रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को, उक्त अंतर और विसंगतियों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, <b>प्रारूप जीएसटी आरईजी-31</b> में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई-मेल पते, या समय-समय पर संशोधित पते पर, इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए।”;</p> <p>(ग) उपनियम (3) में, शब्द, कोष्ठक और अंक “या उपनियम (2)” के पश्चात “शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर या उपनियम (2क)” बढ़ा दिये जायेंगे;</p> <p>(घ) उपनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-</p> <p>“(3क) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (2) या उपनियम (2क) के अधीन निलंबित कर दिया गया हो, उसके रजिस्ट्रीकरण के निलंबित रहने की अवधि के दौरान, धारा 54 के अधीन कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।”;</p> <p>(ङ) उपनियम (4) में, -</p> <p>(i) “शब्द, कोष्ठक और अंक” या उपनियम (2) के पश्चात शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर “या उपनियम (2क)” को बढ़ा दिया जाएगा;</p> <p>(ii) निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-</p> <p>“परंतु इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को समुचित अधिकारी प्रतिसंहरण कर सकता है, रद्दीकरण की प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय यदि वह उचित समझता है तो।”</p>
नियम 22 का संशोधन	<p>उक्त नियमावली में, नियम 22 में,-</p> <p>(क) उपनियम (3) में, शब्द, कोष्ठक और अंक “उपनियम (1) के अधीन जारी किया गया कारण बताओ नोटिस” के पश्चात शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर “या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन” बढ़ा दिये जायेंगे;</p> <p>(ख) उपनियम (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंक “उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत किया गया उत्तर” के पश्चात शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर “या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन जारी नोटिस के उत्तर में” बढ़ा दिये जायेंगे।</p>

<p>7. उक्त नियमावली में, नियम 36 में, उपनियम (4) में, 01 जनवरी, 2021 से</p> <p>(क) दोनों जगह जहां-जहां भी शब्द “अपलोडेड” का उपयोग हुआ है वहां-वहां इसके स्थान पर शब्द “प्रस्तुत” रख दिया जाएगा;</p> <p>(ख) दोनों ही जगहों पर जहां-जहां शब्द कोष्ठक और अंक “धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ताओं के द्वारा” का उपयोग हुआ है वहां-वहां इनके पश्चात शब्द, अक्षर और अंक “<b>प्रारूप जीएसटीआर-1</b> में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए” बढ़ा दिये जायेंगे;</p> <p>(ग) अंक और शब्द “10 प्रतिशत” के स्थान पर अंक और शब्द “5 प्रतिशत” रख दिये जायेंगे।</p>	नियम 36 का संशोधन
<p>8. उक्त नियमावली में, नियम 59 में, उपनियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-</p> <p>“(5) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-</p> <p>(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्रारूप <b>जीएसटीआर- 3ख</b> में विवरणी प्रस्तुत नहीं किया है तो उसे धारा 37 के अधीन प्रारूप <b>जीएसटीआर-1</b> में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अधीन प्रारूप <b>जीएसटीआर-1</b> में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्रारूप <b>जीएसटीआर- 3ख</b> में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।</p> <p>(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसपर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99% से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अधीन प्रारूप <b>जीएसटीआर-1</b> में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्रारूप <b>जीएसटीआर- 3ख</b> में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।</p>	नियम 59 का संशोधन
<p>9. उक्त नियमावली में नियम 86क के पश्चात् 01 जनवरी, 2021 से निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-</p> <p>“<b>86ख. इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध रकम के उपयोग पर प्रतिबंध.-</b> इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उन मामलों में ऐसी कराधेयता के 99% से अधिक आउटपुट कर के लिए अपनी देयता के निष्पादन हेतु इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल नहीं करेगा जहां छूट पूर्ति तथा शून्य दर वाली पूर्ति से भिन्न कराधेय पूर्ति का मूल्य एक माह में पचास लाख रुपये से अधिक है:</p>	उपनियम 86ख का बढ़ाया जाना

	<p>परंतु उक्त प्रतिबंध वहां नहीं लागू होगा, जहाँ—</p> <p>(क) यथास्थिति उक्त व्यक्ति अथवा स्वामी अथवा कर्ता अथवा प्रबंध निदेशक अथवा इसके दो साझीदारों में से कोई एक, पूर्णकालिक निदेशक, संघों की प्रबंध समिति के सदस्य अथवा न्यासी बोर्ड, ने विगत दो वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) के अधीन आय के रूप में एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आयकर विवरणी दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गयी है; अथवा</p> <p>(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (एक) के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदाय रकम एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त की है; अथवा</p> <p>(ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (दो) के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदाय रकम एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त की है; अथवा</p> <p>(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उस रकम के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर के माध्यम से आउटपुट कर के प्रति अपनी देयता का निर्वहन किया है जो चालू वित्तीय वर्ष में उक्त माह तक संचयी रूप से प्रयुक्त कुल आउटपुट कर देयता के 1% से अधिक है; अथवा</p> <p>(ङ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होता है—</p> <p>(i) सरकारी विभाग; अथवा</p> <p>(ii) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम; अथवा</p> <p>(iii) स्थानीय प्राधिकरण; अथवा</p> <p>(iv) सांविधिक निकाय:</p> <p>परंतु यह भी कि आयुक्त अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे सत्यापन तथा ऐसे रक्षोपायों, जिन्हें वह उचित समझे, के उपरांत उक्त प्रतिबंध को हटा सकता है।”</p>
नियम 138 का संशोधन	<p>10. उक्त नियमावली में, नियम 138 में, उपनियम (10) में, 01 जनवरी, 2021 से-</p> <p>(क) तालिका में, स्तंभ 2 में, क्रम सं. 1 के समक्ष, शब्द तथा अंक “100 किमी.” के स्थान पर शब्द तथा अक्षर “200किमी.” रख दिये जायेंगे;</p> <p>(ख) तालिका में, स्तंभ 2 में, क्रम सं. 2 के समक्ष, शब्द तथा अंक “100 किमी.” के स्थान पर शब्द तथा अक्षर “200 किमी.” रख दिये जायेंगे;</p>
नियम 138ङ का संशोधन	<p>11. उक्त नियमावली में नियम 138ङ में,-</p> <p>(क) खण्ड (ख) में, शब्द “दो माह” के स्थान पर, शब्द “दो कर अवधि” रख दिये जायेंगे;</p> <p>(ख) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-</p> <p>“(घ) कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण नियम 21(क) के उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) अथवा उपनियम (2क) के उपबंधों के अधीन निलंबित कर दिया गया है।”</p>
प्रारूप जीएसटी आरईजी-31 का बढ़ाया जाना	<p>12. उक्त नियमावली में प्रारूप <b>जीएसटी आरईजी -30</b> के पश्चात्, निम्नलिखित <b>प्रारूप</b> बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-</p>

## "प्रारूप जीएसटी आरईजी-31 (नियम 21क देखें)

संदर्भ सं.  
सेवा में,

तारीख: <दिन> <माह> <वर्ष>

जीएसटीआईएन:  
नाम:  
पता:

रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करने के लिए सूचना और रद्दीकरण के लिए नोटिस  
निम्नलिखित की तुलना में, यथा,

- (i) अपने माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 39 के अधीन भरे गए विवरणी;
- (ii) अपने प्रारूप **जीएसटीआर -1** में भरे गए वाह्य पूर्तियों का ब्यौरा;
- (iii) अपने आवक पूर्तियों का ऑटो जनरेटेड ब्यौरा;  
\_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक की अवधि से संबंधित;
- (iv) ..... (स्पष्ट करें)

और अन्य उपलब्ध जानकारी के मिलान में निम्नलिखित विसंगति/असंगति का पता चला है:

- ☐ टिप्पणी 1
- ☐ टिप्पणी 2
- ☐ टिप्पणी 3

(करदाता के सुसंगत मानदण्डों के आधार पर भरा जाने वाला ब्यौरा).

2. प्रथम दृष्टया विसंगतियों/असंगतियों से यह प्रकट होता है कि इनसे उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन दर्शित करती है कि यदि इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किये जाने योग्य होगा।

3. इस बात पर विचार करते हुए कि उपर्युक्त विसंगतियाँ/असंगतियाँ इतनी गंभीर हैं और इनसे राजस्व संबंधी हित पर गंभीर खतरा पैदा हुआ है अतः तात्कालिक उपाय के रूप में आपके रजिस्ट्रीकरण को नियम 21क के उपनियम (2क) के अनुसार इस सूचना की तारीख से निलम्बित माना जायेगा।

4. आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले कर अधिकारी के पास अपना उत्तर प्रस्तुत कर दें जिसमें उपर्युक्त विसंगति/असंगति के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध हो। यदि जीएसटी के सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके से आपके दस्तावेजों का दुरुपयोग किये जाने की संभावना हो तो उसको भी विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र वाले अधिकारी की जानकारी में लाया जाये।

5. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजातों के साथ-साथ आपके उत्तर से अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी यदि संतुष्ट होता है और अन्य किसी सत्यापन से जिसे उक्त अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी आवश्यक समझता है तो आपके रजिस्ट्रीकरण के आस्थगन को हटाया जा सकता है।

6. आप कृपया यह नोट कर लें कि यदि आप विनिर्दिष्ट अवधि में अपना उत्तर नहीं देते हैं या कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो आपके रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकता है।

नाम:

पदनाम:

नोट: यह एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस है और इसके जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।"

आज्ञा से,  
आलोक सिन्हा,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 02/XI-2-21-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(172)-2021, dated January 29, 2021 :

No. 02/XI-2-21-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(172)-2021

*Dated Lucknow, January 29, 2021*

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

**Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Forty Eighth Amendment) Rules, 2021**

<b>Short title and commencement</b>	<p>1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Forty Eighth Amendment) Rules, 2021.</p> <p>(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 22nd December, 2020.</p>
<b>Amendment of rule 8</b>	<p>2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, for sub-rule (4A), with effect from a date to be notified, the following sub-rule shall be <i>substituted</i>, namely: -</p> <p>“(4A) Every application made under rule (4) shall be followed by—</p> <p>(a) biometric-based Aadhaar authentication and taking photograph, unless exempted under sub-section (6D) of section 25, if he has opted for authentication of Aadhaar number; or</p> <p>(b) taking biometric information, photograph and verification of such other KYC documents, as notified, unless the applicant is exempted under sub-section (6D) of section 25, if he has opted not to get Aadhaar authentication done,</p> <p>of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in <b>FORM GST REG-01</b> at one of the Facilitation Centres notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this sub-rule.”</p>
<b>Amendment of rule 9</b>	<p>3. In the said rules, in rule 9,-</p> <p>(a) in sub-rule (1), -</p> <p>(i) after the words “applicant within a period of”, for the word “three”, the word “seven” shall be <i>substituted</i>;</p> <p>(ii) for the proviso, the following proviso shall be <i>substituted</i>, namely: -</p> <p>“Provided that where-</p> <p>(a) a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number; or</p>



<p>(b) the proper officer, with the approval of an officer authorised by the Commissioner not below the rank of Assistant Commissioner, deems it fit to carry out physical verification of places of business,</p> <p style="padding-left: 40px;">the registration shall be granted within thirty days of submission of application, after physical verification of the place of business in the presence of the said person, in the manner provided under rule 25 and verification of such documents as the proper officer may deem fit.”;</p> <p>(b ) in sub-rule (2), -</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) for the word “three”, the word “seven” shall be <i>substituted</i>;</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) the following proviso shall be <i>substituted</i>, namely: -</p> <p style="padding-left: 80px;">“Provided that where-</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number; or</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) the proper officer, with the approval of an officer authorised by the Commissioner not below the rank of Assistant Commissioner, deems it fit to carry out physical verification of places of business,</p> <p style="padding-left: 80px;">the notice in <b>FORM GST REG-03</b> may be issued not later than thirty days from the date of submission of the application.”;</p> <p>(c) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be <i>substituted</i>, namely:</p> <p style="padding-left: 40px;">“(5) If the proper officer fails to take any action, -</p> <p style="padding-left: 80px;">(a) within a period of seven working days from the date of submission of the application in cases where the person is not covered under proviso to sub-rule (1); or</p> <p style="padding-left: 80px;">(b) within a period of thirty days from the date of submission of the application in cases where a person is covered under proviso to sub-rule (1); or</p> <p style="padding-left: 80px;">(c) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2),</p> <p style="padding-left: 40px;">the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.”</p>	
<p>4. In the said rules, in rule 21,-</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) in clause(b), after the words “goods or services”, the words “or both” shall be <i>inserted</i>;</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) after clause (d), the following clauses shall be <i>inserted</i>, namely:-</p> <p style="padding-left: 80px;">“(e) avails input tax credit in violation of the provisions of section 16 of the Act or the rules made there under; or</p> <p style="padding-left: 80px;">(f) furnishes the details of outward supplies in <b>FORM GSTR-1</b> under section 37 for one or more tax periods which is in excess of the outward supplies declared by him in his valid return under section 39 for the said tax periods; or</p> <p style="padding-left: 80px;">(g) violates the provision of rule 86B.”</p>	<p><b>Amendment of rule 21</b></p>

Amendment of rule 21A	<p>5. In the said rules, in rule 21A,-</p> <p>(a) in sub-rule (2), the words “,after affording the said person a reasonable opportunity of being heard,” shall be <i>omitted</i>;</p> <p>(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be <i>inserted</i>, namely: -</p> <p>“(2A) Where, a comparison of the returns furnished by a registered person under section 39 with</p> <p>(a) the details of outward supplies furnished in <b>FORM GSTR-1</b>; or</p> <p>(b) the details of inward supplies derived based on the details of outward supplies furnished by his suppliers in their <b>FORM GSTR-1</b>,</p> <p>or such other analysis, as may be carried out on the recommendations of the Council, show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder, leading to cancellation of registration of the said person, his registration shall be suspended and the said person shall be intimated in <b>FORM GST REG-31</b>, electronically, on the common portal, or by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said differences and anomalies and asking him to explain, within a period of thirty days, as to why his registration shall not be cancelled.”;</p> <p>(c) in sub-rule (3), after the words, brackets and figure “or sub-rule (2)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (2A)” shall be <i>inserted</i>;</p> <p>(d) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be <i>inserted</i>, namely: -</p> <p>“(3A) A registered person, whose registration has been suspended under sub-rule (2) or sub-rule (2A), shall not be granted any refund under section 54, during the period of suspension of his registration.”;</p> <p>(e) in sub-rule (4), -</p> <p>(i) after the words, brackets and figure “or sub-rule (2)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (2A)” shall be <i>inserted</i>;</p> <p>(ii) the following proviso shall be <i>inserted</i>, namely: -</p> <p>“Provided that the suspension of registration under this rule may be revoked by the proper officer, anytime during the pendency of the proceedings for cancellation, if he deems fit.”.</p>
Amendment of rule 22	<p>6. In the said rules, in rule 22,-</p> <p>(a) in sub-rule (3), after the words, brackets and figure “the show cause issued under sub-rule (1)”, the words, brackets, figures and letters “or under sub-rule (2A) of rule 21A” shall be <i>inserted</i>;</p> <p>(b) in sub-rule (4), after the words, brackets and figure “reply furnished under sub-rule (2)”, the words, brackets, figures and letters “or in response to the notice issued under sub-rule (2A) of rule 21A” shall be <i>inserted</i>.</p>
Amendment of rule 36	<p>7. In the said rules, in rule 36, in sub-rule (4), with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2021,-</p> <p>(a) for the word “uploaded”, at both the places where it occurs, the word “furnished” shall be <i>substituted</i>;</p> <p>(b) after the words, brackets and figures “by the suppliers under sub-section (1) of section 37”, at both the places where they occur, the words, letters and figure “in <b>FORM GSTR-1</b> or using the invoice furnishing facility” shall be <i>inserted</i>;</p> <p>(c) for the figures and words “10 per cent.”, the figure and words “5 per cent.” shall be <i>substituted</i>.</p>

<p>8. In the said rules, in rule 59, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be <i>inserted, namely:</i> -</p> <p>“(5) Notwithstanding anything contained in this rule, -</p> <p>(a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in <b>FORM GSTR-1</b>, if he has not furnished the return in <b>FORM GSTR-3B</b> for preceding two months;</p> <p>(b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to sub-section (1) of section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in <b>FORM GSTR-1</b> or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in <b>FORM GSTR-3B</b> for preceding tax period;</p> <p>(c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine per cent. of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in <b>FORM GSTR-1</b> or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in <b>FORM GSTR-3B</b> for preceding tax period.”.</p>	<p><b>Amendment of rule 59</b></p>
<p>9. In the said rules, after rule 86A, with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2021, the following rule shall be <i>inserted, namely:</i> -</p> <p><b>“86B. Restrictions on use of amount available in electronic credit ledger.</b>-Notwithstanding anything contained in these rules, the registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of ninety-nine per cent. of such tax liability, in cases where the value of taxable supply other than exempt supply and zero-rated supply, in a month exceeds fifty lakh rupees:</p> <p>Provided that the said restriction shall not apply where –</p> <p>(a) the said person or the proprietor or karta or the managing director or any of its two partners, whole-time Directors, Members of Managing Committee of Associations or Board of Trustees, as the case may be, have paid more than one lakh rupees as income tax under the Income, Tax Act, 1961 (Act no. 43 of 1961) in each of the last two financial years for which the time limit to file return of income under subsection (1) of section 139 of the said Act has expired; or</p> <p>(b) the registered person has received a refund amount of more than one lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilised input tax credit under clause (i) of first proviso of sub-section (3) of section 54; or</p> <p>(c) the registered person has received a refund amount of more than one lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilised input tax credit under clause (ii) of first proviso of sub-section (3) of section 54; or</p> <p>(d) the registered person has discharged his liability towards output tax through the electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability, applied cumulatively, upto the said month in the current financial year; or</p> <p>(e) the registered person is –</p> <p>(i) Government Department; or</p> <p>(ii) a Public Sector Undertaking; or</p> <p>(iii) a local authority; or</p> <p>(iv) a statutory body:</p> <p>Provided further that the Commissioner or an officer authorised by him in this behalf may remove the said restriction after such verifications and such safeguards as he may deem fit.”.</p>	<p><b>Insertion of rule 86B</b></p>

<b>Amendment of rule 138</b>	10. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (10), with effect from the 1 <sup>st</sup> day of January, 2021,-  (a) in the Table, against serial number 1, in column 2, for the figures and letters “100 km.”, the figures and letters “200 km.” shall be <i>substituted</i> ;  (b) in the Table, against serial number 2, in column 2, for the figures and letters “100 km.”, the figures and letters “200 km.” shall be <i>substituted</i> .
<b>Amendment of rule 138E</b>	11. In the said rules, in rule 138E, -  (a) in clause (b), for the words “two months”, the words “two tax periods” shall be <i>substituted</i> ;  (b) after clause (c), the following clause shall be <i>inserted</i> , namely:-  “(d) being a person, whose registration has been suspended under the provisions of sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (2A) of rule 21A.”
<b>Insertion of FORM GST REG-31</b>	12. In the said rules, after <b>FORM GST REG-30</b> , the following FORM shall be <i>inserted</i> , namely-

**“FORM GST REG – 31**

[See rule 21A]

Reference No.

Date: &lt;DD&gt;&lt;MM&gt;&lt;YYYY&gt;

To,

GSTIN

Name:

Address:

**Intimation for suspension and notice for cancellation of registration**

In a comparison of the following, namely,

- (i) returns furnished by you under section 39 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017;
- (ii) outwards supplies details furnished by you in **FORM GSTR-1**;
- (iii) auto-generated details of your inwards supplies for the period \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_;
- (iv)..... (specify)

and other available information, the following discrepancies/ anomalies have been revealed:

- ☐ Observation 1
- ☐ Observation 2
- ☐ Observation 3

(details to be filled based on the criteria relevant for the taxpayer).

2. These discrepancies/anomalies prima facie indicate contravention of the provisions of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder, such that if not explained satisfactorily, shall make your registration liable to be cancelled.

3. Considering that the above discrepancies/anomalies are grave and pose a serious threat to interest of revenue, as an immediate measure, your registration stands suspended, with effect from the date of this communication, in terms of sub-rule (2A) of rule 21 A.

4. You are requested to submit a reply to the jurisdictional tax officer within thirty days from the receipt of this notice, providing explanation to the above stated discrepancy/ anomaly. Any possible misuse of your credentials on GST common portal, by any person, in any manner, may also be specifically brought to the notice of jurisdictional officer.

5. The suspension of registration shall be lifted on satisfaction of the jurisdictional officer with the reply along with documents furnished by you, and any further verification as jurisdictional officer considers necessary.

6. You may please note that your registration may be cancelled in case you fail to furnish a reply within the prescribed period or do not furnish a satisfactory reply.

Name:

Designation:

NB: This is a system generated notice and does not require signature by the issuing authority.”.

By order,  
ALOK SINHA,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 755 राजपत्र-2021-(1564)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 77 सा0 राज्य कर-2021-(1565)-1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।